

## बिहार को 'वशेष राज्य' का दर्जा देने से इनकार

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र ने सर्वदलीय बैठक के दौरान बिहार के लिये 'वशेष श्रेणी' का दर्जा देने के अनुरोध को खारजि कर दिया।

### प्रमुख बडि:

- वर्तमान में किसी भी नए राज्य को 'वशेष श्रेणी' का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि [भारतीय संवधान](#) में इस तरह के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है।
  - **बिहार वशेष राज्य का दर्जा और अलग वतितीय पैकेज दोनों की मांग कर रहा है।** बिहार के लिये वशेष दर्जे की मांग तब से जारी है जब राज्य का वभिजन बिहार तथा झारखंड में हुआ था।
- [गाडगलि फारमूला](#):
  - वशेष श्रेणी के दर्जे के मुद्दे पर पहली बार वर्ष 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council- NDC) की बैठक में चर्चा की गई थी। इस सत्र के दौरान, [D.R. गाडगलि समिति](#) ने भारत में राज्य योजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता वतिरति करने का एक सूत्र प्रस्तावति कथिा था
    - इससे पहले, नधि आवंटन के लिये कोई वशिषिट फारमूला नहीं था और अनुदान व्यक्तगित योजनाओं के आधार पर आवंटति कथिा जाता था।
  - गाडगलि फारमूले, जसिे NDC की मंजूरी मलिी थी, ने केंद्रीय सहायता के आवंटन में असम, जममू-कश्मीर और नगालैंड जैसे वशेष श्रेणी के राज्यों की ज़रूरतों को प्राथमकिता दी।
  - वर्ष 1969 में [पांचवें वतित आयोग](#) ने कुछ क्षेत्रों के समक्ष मौजूद ऐतहिासकि चुनौतियों को स्वीकार कथिा और वशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान कथिा
    - इस सुझाव से वशिषिट वंचति राज्यों को केंद्रीय सहायता और कर राहत सहति वशेष लाभ प्राप्त हुए
    - इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस स्थतिके आधार पर इन राज्यों को केंद्रीय योजना सहायता आवंटति की।
  - वतितीय वर्ष 2014-2015 तक वशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त 11 राज्यों को वभिनिन लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त थे।
    - हालाँकि वर्ष 2015 में [योजना आयोग](#) के वधिटन और [नीति आयोग](#) की स्थापना के साथ [14वें वतित आयोग](#) की सफिरशिों के परिणामस्वरूप गाडगलि फारमूले पर आधारति अनुदान बंद हो गए।
    - परिणामस्वरूप, सभी राज्यों को आवंटति वभिज्य पूल का हसिसा 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया।